कोटद्वार, रविवार
30 जून 2024
वर्षः 46
अंकः 67 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

पूर्वांचल रूट को मिली दो समर स्पेशल ट्रेनों की सौगात

रुड़की। पूर्वांचल की ट्रेनों में पिछले महीने से ही भारी भीड़ चल रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने दरभंगा से सरहिंद और पूर्णिया कोर्ट से सरहिंद के लिए दो और समर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इनसे छुट्टियों में परिवार संग घर गए पूर्वांचल के लोगों को लौटने में आसानी हुई है। पूर्वांचल के सैकड़ों परिवार लक्सर और आसपास रहकर काम करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में ये घर गए थे। अब ये लौट रहे हैं। इनके लिए रेलवे ने दो समर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। पहली समर स्पेशल सरहिंद से 29 जून में तड़के 6:30 बजे चली है। ये राजपुरा, अंबाला कैंट, यमुनानगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, कमतौल स्टेशनों पर रुककर 30 जून सुबह 10 बजे दरभंगा स्टेशन पहुंचेगी। दरभंगा से ये 05581 अप ट्रेन 28 जून सुबह 5:30 बजे चलकर इन्हीं स्टेशन से होते हुए शनिवार तड़के 4:30 बजे सरहिंद पहुंची है। दूसरी समर स्पेशल 28 जून रात 8 बजे पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से चली है, और बनमंखी, मुरलीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सीमरी बख्तियारपुर, मानसी जंक्शन, खगड़िया, हसनपुर रोड, समस्तीपुर, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनवां, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनागर, अंबाला कैंट, राजपुरा स्टेशन पर रुकने के बाद 30 जून रात 3 बजे सरहिंद पहुंचेगी।

इधर से ये ट्रेन 30 जून तड़के 5 बजे चलकर इसी रूट से 1 जुलाई तड़के 3:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। लक्सर में काम करने वाले गोरखपुर निवासी राजीव प्रसाद, कमलेश यादव ने बताया कि वे गर्मी की छुट्टी में परिवार संग घर गए थे। इधर से उन्हें तत्काल में रिजर्वेशन मिला था। उधर से गाड़ियों में सीट खाली नहीं थी। इसलिए वे तत्काल से वापसी का आरक्षण कराने का इंतजार कर रहे थे। पर इन ट्रेनों में उन्हें आसानी से आरक्षण मिल गया है। इससे वे कम पैसे में काम पर वापस लौट आए हैं।

सांख्यिकी का उपचार एवं मेडिकल शोध में अहम योगदान

देहरादून।दून मेडिकल कॉलेज में शनिवार को प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना के निर्देशन में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से सांख्यिकी दिवस मनाया गया। एचओडी डॉ. अनुपमा आर्या के नेतृत्व में निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राचार्य डॉ. सयाना ने सभी को बधाई दी। मेडिकल पीजी के छात्र–छात्राओं से उन्होंने सांख्यिकी पर विस्तृत अध्ययन की अपील की। कहा कि शोध में यह मददगार साबित होगी। एचओडी डॉ. आर्या, सांख्यिकीविद् डॉ. सोनम माहेश्वरी ने सांख्यिकी की विभिन्न तकनीकों एवं पद्धतियों पर वयाख्यान दिया। इस दौरान डॉ. शिव कुमार, डॉ. ऋचा सिन्हा, डॉ. प्रियंका डोभाल, डॉ. सुमित, डॉ. शालिनी, डॉ. सुदीक्षा, डॉ. रश्मि, एमएसडब्लयू महादेव गौड, रमेश ध्यानी आदि मौजूद रहे।

लद्दाख में नदी पार करने का अभ्यास कर रहे टैंक सवार जवान बहे

दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैंक से श्योक नदी पार करने के अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में जेसीओ सहित पांच जवान की जान चली गई। यह दुर्घटना रात एक बजे के करीब चुशूल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुई। नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते यह हादसा हुआ। रक्षा प्रवक्ता पीएस सिंधु अनुसार तथ्यों की जांच चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास सेना के जवान टी–72 टैंक में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नदी के बढ़ते जलस्तर ने आसपास की जगह को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। टैंक भी तेजी के साथ तेज बहाव की चपेट में आने लगा।

सेना के जवानों की कड़ी कोशिश के बाद भी टैंक से नियंत्रण कम होता गया। ऐसे में तेज बहाव का पानी सेना के पांच जवानों और टैंक को बहा कर ले गया। हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत सेना की अन्य टीमें मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाढ़ के पानी के बीच बचाव कार्य चलाना चुनौतियों से भरा था।

नए कानून से पीड़ित को अधिक अधिकार के साथ जल्द मिलेगा न्याय

● 1 जुलाई 2024 से लागू होगें तीन नए कानून ● -मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेश-क अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।

प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किये गये प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इनके प्रचार-प्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए। पुलिस महानिदेशक द्वारा नये कानूनों की आवश्यकता के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को न्याय पाना एवं आवाज उठा पाना कठिन था। सहिंता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना तथा भारतीय नागरिकों का दमन करना था। पूर्ववर्ती कानूनों के फलस्वरूप न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, दोषसिद्धि की कम दर, पीड़ित की असंतुष्टि एवं अपराधी पर अपूर्ण कार्यवाही रहा। इसी के मद्देनजर नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है।

रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना भारत

● 17 साल का खिताबी सूखा समाप्त, चूर–चूर हुए साउथ अफ्रीकी अरमान

नई दिल्ली। जिस चमचमाती ट्रॉफी का इंतजार पूरा हिन्दुस्तान सालों से कर रहा था वो भारत के हिस्से आ चुकी है। भारत ने शनिवार को केनसिंग्टन ओवल में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप–2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को सात रनों से हरा खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और सात विकेट खोकर 176 रन बनाए। अपना पहला फाइनल मैच खेल रही साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी लड़ाई लड़ी लेकिन ये टीम 20 ओवरों में 169 रन ही बना सकी और खिताब से महरूम रह गई।

भारत दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। भारत ने पहली बार साल 2007 में ये ट्रॉफी जीती थी। इसी के साथ भारत तीसरी टीम बन गई है जिसने टी20 का खिताब दूसरी बार जीता है। उससे पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के काम कर चुके हैं। भारत ने साल 2013 से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे और 17 साल से चले आ रहे टी20 वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म कर दिया।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माकपा की भूमि बैंक में पड़े 73 लाख जब्त किए

वामपंथी दल ने आरोपों से किया इन्कार

नई दिल्ली। ईडी ने केरल में एक बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माकपा की एक जमीन और बैंक में जमा 73 लाख रुपये को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। जबकि वामपंथी दल ने कहा कि इस मामले से कानूनी और राजनीतिक रूप से निपटेंगे।

माकपा पर ईडी ने कसा शिकंजा

सूत्रों के अनुसार, इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अंतरिम आदेश जारी किया गया। जब्त की गई संपत्तियों में केरल के त्रिशूर जिले में 10 लाख रुपये मूल्य का भूखंड और राजनीतिक दल के अघोषित बैंक खाते में जमा 73 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और संस्थाओं की 28.65 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। इधर, माकपा ने ईडी के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह करोड़ों रुपये के कथित करुवन्नूर बैंक घोटाले से संबंधित मामले में उसे आरोपी बनाने की जांच एजेंसी के किसी भी कदम का कानूनी और राजनीतिक रूप से निपटेगी।

ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित

पार्टी के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विभिन्न मामलों में विपक्षी दलों एवं उनके नेताओं को आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है। जबकि ईडी का मानना है कि उसने जो भूखंड जब्त किया है, वह माकपा के पार्टी कार्यालय के लिए था और उसे ऋणधारकों या करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऋण के लाभार्थियों से मिली कथित रिश्वत से खरीदा गया था।

दून के मुख्य डाकघर में खुला प्लास्टिक बैंक

देहरादून। एसडीसी फाउंडेशन ने घंटाघर स्थित मुख्य डाकघर (जीपीओ) परिसर में भी प्लास्टिक बैंक की स्थापना कर दी है। इस प्लास्टिक बैंक में पोस्ट ऑफिस के साथ ही इस परिसर में कार्यरत डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों का प्लास्टिक कचरा भी कलेक्ट किया जाएगा। प्रवर डाकपाल टिकम्बर सिंह गुसाईं ने कहा कि एसडीसी फाउंडेशन की ओर से शुरू किया गया प्लास्टिक बैंक प्रोजेक्ट पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत एक सराहनीय प्रयास है। पोस्ट ऑफिस के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उक्त प्रोजेक्ट से जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

फाउंडेशन के दिनेश सेमवाल ने कहा कि अभी तक दून में 135 प्लास्टिक बैंक स्थापित हो चुके हैं। अब मुख्य पोस्ट ऑफिस में प्लास्टिक बैंक की स्थापना एक नई पहल है। पोस्ट ऑफिस के विभिन्न विभागों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के अलावा इस प्लास्टिक बैंक में इस परिसर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों का प्लास्टिक कचरा भी कलेक्ट किया जाएगा।

पुलिस, जांच और न्यायिक व्यवस्था का बदलेगा चेहरा

नई दिल्ली। नई आपराधिक न्याय प्रणाली में सुगम और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रविधान किये गए हैं। लेकिन इसे पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए मशक्कत करनी होगी। पूरी तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक पर ज्यादा जोर देने वाली इस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने में चुनौतियां भी अपार है।

सभी थानों और अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की सुचारू आपूर्ति, पावर बैकअप की व्यवस्था, क्राइम सीन से सबूत जुटाने के लिए सभी जिलों में पर्याप्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती और मोबाइल फॉरेंसिक बैन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में समय लग सकता है।

इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता पर जोर

वहीं, सीसीटीएनएस ई–कोर्ट, ई–फॉरेंसिक, ई–प्रिजन और ई–प्रोसेक्यूशन पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने वाले डाटा को क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती भी होगी। नए आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा।

वैसे भारतनेट के सहारे सभी पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या बरकरार है। जबकि न्यायश्रुति एप से गवाही, ई–साक्ष्य पर सबूतों को अपलोड करने और अदालतों में डिजिटल सुनवाई के कनेक्टिविटी सबसे अहम है। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बिजली की अबाध आपूर्ति और बिजली कटने की स्थिति में पावर बैकअप की व्यवस्था भी अहम होगी।

अदालती सुनवाई हो सकती है प्रभावित

पिछले एक दशक में बिजली की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और सरकार लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्धता का दावा कर रही है। लेकिन गर्मी में ज्यादा मांग के समय कई इलाकों में घंटों बिजली कटौती की शिकायतें भी मिल रही है। ऐसी स्थिति पुलिस जांच से लेकर अदालती सुनवाई तक प्रभावित हो सकती है।

नए आपराधिक कानूनों में फॉरेंसिक पर अत्यधिक जोर है। इसके लिए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की जरूरत पड़ेगी। देश में कुल 885 पुलिस जिले हैं, जिनमें इस साल जनवरी तक केवल 75 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध था। तीन कंपनियों के मोबाइल फॉरेंसिक वैन के डिजाइन को मंजूरी दी गई थी और राज्यों को इन्हें खरीदने को कहा गया था। लेकिन अभी तक ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि पिछले छह महीने में कितने मोबाइल फॉरेंसिक वैन खरीदे गए और कितने जिलों में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित

इसी तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 19 जून को 2254 करोड़ के प्रोजेक्ट के मंजूरी दी है। इसके तहत सभी राज्यों में नेशनल फॉरेंसिक साइसेंस यूनिवर्सिटी के कैंपस सभी राज्यों में खोले जाएंगे।

जाहिर कैंपस खुलने और उनसे प्रशिक्षित एक्सपर्ट के निकलने में समय लगेगा। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद केस जुड़े सबूतों, बयानों, जांच रिपोर्ट, अदालती सुनवाई का डाटा बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा।

घर बनाना होगा पहले से ज्यादा महंगा

– दून में रेत और बजरी 40 से 45 फीसदी तक महंगी, पीवीसी पाइप भी 10 फीसदी महंगा हुआ

देहरादून। बारिश शुरू होते ही दून में रेत और बजरी 40 से 45 फीसदी तक महंगी हो गई है। इस कारण भवन निर्माण की लागत एक से दो फीसदी तक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में रेत और बजरी की कीमत और बढ़ने की आशंका है। बरसात में अमूमन नदियों का पानी बढ़ने से खनन नहीं हो पाता। इससे रेत–बजरी की किल्लत शुरू हो जाती है। लेकिन, इस साल अभी नदियां उफान पर भी नहीं आई हैं और रेत–बजरी के रेट बढ़ने लगे हैं। दरअसल, कई जगह अभी से रेत–बजरी को डंप किया जाने लगा है, ऐसे में बाजार में किल्लत बढ़ गई है। कॉन्ट्रेक्टर प्रकाश जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में रेत की कीमत 90 रुपये से बढ़कर 130 रुपये कुंतल तक पहुंच गई है। रेत में सीधा–सीधा 40 रुपये प्रति कुंतल तक का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार बजरी भी 95 रुपये से बढ़कर 135 रुपये कुंतल तक पहुंच गई है।पीवीसी पाइप भी 10 फीसदी महंगा भवन निर्माण में उपयोग होने वाले पीवीसी पाइप की कीमत में भी 10 फीसदी तक बढ़ गई। सप्ताहभर पहले पीवीसी पाइप का बंडल (25 पाइप) 1700 रुपये का था, जो अब बढ़कर 1900 रुपये का हो गया है। बता दें कि पीवीसी पाइप का उपयोग भवनों में पानी और बिजली की फिटिंग में किया जाता है।

आम आदमी पर इस तरह पड़ेगा आर्थिक भार

रेत–बजरी महंगी होने से आम आदमी पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। कॉन्ट्रेक्टर प्रकाश जायसवाल और सुमित रघुवंशी ने बताया कि 100 गज जमीन पर एक दोमंजिला भवन का निर्माण करीब 35 लाख रुपये में होता है। इसमें करीब 30 से 40 टन रेत और 50 से 60 टन बजरी उपयोग होती है। लेकिन, अब रेट बढ़ने के कारण 30 टन रेत 27000 हजार की तुलना में अब 39000 रुपये की पड़ेगी। इसी प्रकार 50 टन बजरी की कीमत 47500 से बढ़कर 67500 रुपये हो जाएगी। आने वाले दिनों में रेत–बजरी की कीमतें 150 रुपये कुंतल से अधिक पहुंच सकती हैं।

तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ दर्दनाक हादसा, पटाखा फैक्टरी में भीषण धमाका, 3 की मौत एक घायल

विरुधुनगर (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। विरुधुनगर के जिला कलेक्टर ने कहा कि विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं एक घायल हो गया। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले पर आगे की जानकारी का इंतजार है।

पिछले महीने भी हुआ था एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट

बता दें कि पिछले महीने विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास नारायणपुरम पुदुर में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था।

नीट पर चर्चा से भाग रही कांग्रेस', विपक्ष के हंगामे पर बोले धर्मेंद्र प्रधान

जल्द होगा परीक्षा की नई तारीखों का एलान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि सरकार मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली नीट–यूजी परीक्षा पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह परंपरा के अनुसार और मर्यादा में रहते हुए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और वे इससे भाग रहे हैं। वे केवल अराजकता और भ्रम चाहते हैं और संस्थागत तंत्र के पूरे कामकाज में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं।

प्रधान ने कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, उस पर राष्ट्रपति ने खुद बात की है। उन्होंने प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों को स्वीकार किया है और कहा है कि हमें उन पर गौर करना होगा। प्रधान ने कहा कि सरकार की ओर से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वे चाहते हैं कि मामला इसी तरह से उलझा रहे।

नीट मुद्दे पर छात्रों को भ्रमित कर रही कांग्रेस

प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत में अपील की कि छात्रों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 2014 से पहले भी ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन मैं इसे सही नहीं ठहरा सकता... एनटीए को नया नेतृत्व मिला है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एनटीए में सुधार शुरू किए गए हैं, हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नया कानून बनाया है और पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल परीक्षा तिथियों का एक नया सेट घोषित किया गया था। जिसे बाद में रद कर दिया गया था। नीट–पीजी की नई तिथियों की घोषणा सोमवार–मंगलवार तक की जाएगी।

सरकारी स्कूलों में एडमिशन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

,नई दिल्ली। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में आ गई है। 2016 में पकड़े गए चार लाख फर्जी छात्रों के मामले में एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद उइक एक्शन मोड में

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2019 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए।

चार लाख फर्जी दाखिले मिले

हाईकोर्ट को 2016 में सूचित किया गया था कि आंकड़ों के सत्यापन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए और चार लाख फर्जी दाखिले थे।

अदालत को यह भी बताया गया कि समाज के पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूलों और मिड डे मील योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभ दिए जा रहे हैं।

फर्जी छात्रों के नाम पर धन की हेराफेरी

उच्च न्यायालय ने राज्य सतर्कता विभाग को चार लाख फर्जी छात्रों के नाम पर धन की संदिग्ध हेराफेरी की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पीठ ने जिम्मेदारी तय करने और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सतर्कता ब्यूरो की सिफारिशों पर राज्य में सात एफआईआर दर्ज की गईं।

शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती, पति जहीर के साथ पिता का हालचाल लेने पहुंचीं सोनाक्षी

दिल्ली। नई–नवेली दुल्हन सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल को शुक्रवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर देखा गया। शादी के महज पांच दिन बाद कपल को अस्पताल के बाहर देख फैंस तरह–तरह के कयास लगाने लगे। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा इस अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में उनका हालचाल लेने के लिए जहीर और सोनाक्षी वहां पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा उम्र संबंधी रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल – फोटो : इंस्टाग्राम

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून को रजिस्टर मैरिज की। करीब सात साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश किया है। दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई और इसके बाद शाम को रिसेप्शन पार्टी का आयोजन हुआ। बेटी की विदाई के पांच दिन बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोनाक्षी के पिता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत ठीक नहीं है। उम्र संबंधी रूटीन जांच के लिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में सोनाक्षी अपने पति जहीर के साथ पिता से मिलने अस्पताल पहुंचीं।

सोनाक्षी और जहीर की शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार 26 जून को शादी की कुछ छलकियां सोशल मीडिया पर साझा कीं।

बढ़ती महंगाई और सरकारी आंकड़ों की भूलभुलैया

प्रो० सी० एस० बरला

पिछले दो वर्षों में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि 2022–23 के बीच विश्व में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 69 करोड़ से बढ़कर 78। 3 करोड़ हो गई। इसका यह अर्थ हुआ कि 2023 में विश्व की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित थी। इसी के विपरीत भारत में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा उपभोक्ता व्यय पर एकत्रित आंकड़ों से ज्ञात हुआ था कि 2011–12 तथा 2022–23 के बीच शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों का उपभोग पर किया जाने वाले व्यय का जिनी गुणांक कम हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस अवधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय की विषमताओं में कमी हुई है।

उपभोक्ता व्यय के तथ्य : जिनी गुणांक विभिन्न वर्गों के बीच उपभोक्ता व्यय की विषमताओं का प्रतीक है। यह गुणांक जितना अधिक है उसका आशय यह है कि कुछ ही व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का अधिक भाग व्यय करते हैं। परोक्ष रूप में यह देश में व्याप्त गरीबी के उच्च स्तर का प्रतीक है। अन्य शब्दों में, उपभोक्त व्यय का जिनी गुणांक यदि कम है तो यह गरीबों के कम स्तर का परिचायक होगा। भारत के नीति आयोग के प्रमुख इसी आधार पर यह निष्कर्ष देते हैं कि 2011–12 तथा 2022–23 के बीच भारत में गरीबों का अनुपात 5त्न से कम हो गया। 2011–12 में शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता का जिनी गुणांक 0.363 था और 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय का जिनी गुणांक 0.283 था। 2022–23 में शहरी क्षेत्र का जिनी गुणांक 0.314 था और 2022–23 में ग्रामीण क्षेत्र का जिनी गुणांक 0। २८६ था। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में उपभोक्ता व्यय में कमी हुई है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे से यह बात सामने आई कि आलोच्य अवधि में उपभोक्ता परिवारों में निचले 50 प्रतिशत परिवारों की उपभोक्ता व्यय के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक अच्छा संकेत भी माना जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता परिवारों में हम जितनी नीचे की पायदान पर जाएंगे हमें निर्धन लोग ही अधिक दिखाई देंगे।

राज्यवार उपभोक्ता व्यय में अंतरः इस तथ्य को एनएसएसओ ने स्वीकार किया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों तथा उपभोक्ताओं की आदतों में पर्याप्त अंतर होने के कारण सारे राज्यों के परिवारों के उपभोक्ता व्यय की तुलना करने में कठिनाई होती है। इसका एक समाधान प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय की तुलना द्वारा हो सकता है। इन स्तरों में भी विभिन्न राज्यों में काफी विषमताएं हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय 2468 रुपए है जबकि शहर में इसका स्तर 4462 रुपए है। इसके विपरीत केरल में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 2920 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 8175 रुपए है।

अस्तु, उपभोक्ता व्यय के जिनी गुणांक में कमी या वृद्धि से यह तो ज्ञात हो सकता है कि उपभोक्ता व्यय के वितरण में विषमताएं बढ़ीं या कम हुईं लेकिन इसकी सार्थकता कितनी है तथा नीति निर्धारण में यह कहां तक उपयोगी है, यह कहना संभव नहीं है। परिवारों के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों का स्तर कितना है तथा उसकी आय के स्तर में अनुपात कितना है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता व्यय के आंकड़े हमारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है।मुद्रास्फीति का आकलनः हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में देश में खुदरा महंगाई में कमी हुई है, जबकि थोक महंगाई में वृद्धि हुई है। एक आम व्यक्ति के लिए यह एक पहेली है। वह इन आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय नहीं कर पाता कि मुद्रास्फीति की यह दर उसके लिए प्रतिकूल है अथवा अनुकूल। वस्तुतः खुदरा तथा थोक मूल्य सूचकांकों की गणना करते समय न केवल वस्तुओं की संख्या में अंतर है और न ही मूल्य में समरूपता है। इस कारण स्थिति के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती। आवश्यकता इस बात की है कि सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में समरूपता लाई जाए जिससे आम व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे ।

सख्त कानून लागू

सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर दिया है। इस एंटी–पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक या उत्तर–पुस्तिका से छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल की सजा होगी जिसे दस लाख तक के जुर्माने के साथ बढ़ा कर पांच साल तक भी किया जा सकता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार महीने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे चुकी थीं। इस कानून का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित अन्य तमाम परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है।

इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अब न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून से पहले राज्यों में नकल रोकने और परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने संबंधी कानून बनाए गए हैं।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में ऐसे कानून हैं। हालांकि ये उस तरह के नतीजे देने में असफल रहे हैं, जिनके बलबूते परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जा सके।

इस नये कानून द्वारा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रमुख और सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा ताकि उनके खिलाफ अपराध के साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी चलाया जा सके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठने वाली उंगलियों के कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है।

मोदी गठबंधन पूर्व गठबंधन सरकारों से अलग

भारत में गठबंधन सरकारों के काम करने और उसके संचालन का अनुभव बहुत अच्छा नही रहा है। गठबंधन में सरकार का नेतृत्व करने वाले दल और नेता पर साथी दल अधिक से अधिक मंत्री बनाने और जिन्हें वो चाहते हैं उन्हें मंत्री के रूप में स्वीकार करने तथा बाद में अपने अनुसार नीतियां बनवाने या बदलवाने के लिए दबाव डालते रहें। अपनी बात न मानने पर समर्थन वापसी तथा सरकार के अस्थिर होने, गिर जाने, कमजोर हो जाने की घटनाएं भी हमने देखी हैं। जानते और चाहते हुए भी कई बार प्रधानमंत्री को नीतियों के स्तर पर वैसे कदम उठाने से स्वयं को रोकना पड़ा या उठाए हुए कदम वापस लेने पड़े जो देश के लिए आवश्यक थे। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान गठबंधन सरकार को लेकर कोई आशंका उठती है तो उसे इस पृष्ठभूमि में तत्काल खारिज भी नही किया जा सकता।

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है । भारत में गठबंधन सरकारों के काम करने और उसके संचालन का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। गठबंधन में सरकार का नेतृत्व करने वाले दल और नेता पर साथी दल अधिक से अधिक मंत्री बनाने और जिन्हें वो चाहते हैं उन्हें मंत्री के रूप में स्वीकार करने तथा बाद में अपने अनुसार नीतियां बनवाने या बदलवाने के लिए दबाव डालते रहें। अपनी बात न मानने पर समर्थन वापसी तथा सरकार के अस्थिर होने, गिर जाने, कमजोर हो जाने की घटनाएं भी हमने देखी हैं।

जानते और चाहते हुए भी कई बार प्रधानमंत्री को नीतियों के स्तर पर वैसे कदम उठाने से स्वयं को रोकना पड़ा या उठाए हुए कदम वापस लेने पड़े जो देश के लिए आवश्यक थे। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान गठबंधन सरकार को लेकर कोई आशंका उठती है तो उसे इस पृष्ठभूमि में तत्काल खारिज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि विपक्ष इसे कमजोर व लंगड़ी सरकार बता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह टिप्पणी कर रहा है कि वे शेर से बकरी हो गए हैं तो उससे पूछा जाना चाहिए कि इसके समानांतर अगर सत्ता में वे आते तो उनकी सरकार कैसी होती? कम से कम इस सरकार में एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसके आसपास भी कोई दल नहीं। राहुल गांधी जी के शब्दों में अगर यह क्रिप्पल्ड सरकार है तो ह्यइंडियाह्ल की सरकार क्या ठोस चट्टान वाली होती?

कहने का तात्पर्य कि हमें आशंकाओं या विपक्ष की अतिवादी आलोचनाओं में जाने की जगह वास्तविकताओं के आधार पर इसके वर्तमान एवं भविष्य का आकलन करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए कि आखिर अब मंत्रिमंडल गठन के बाद सरकार कैसे काम करेगी? सरकार की दिशा और दशा क्या होगी? यह बात सही है कि हमने पिछले 10 वषी में ऐसी मोदी सरकार देखी है जिसके पास अपनी भाजपा का बहुमत था और ऐसे बड़े फैसले हुए, कदम उठाए गए, संवैधानिक–प्रशासनिक एवं नीतियों के स्तर पर ऐसे आमूल बदलाव के निर्णय हुए जिनकी पहले कल्पना नहीं थी। स्वयं सरकार को और देश को 10 वषी के इस अभ्यास से बाहर निकालना कठिन होगा, लेकिन क्या वाकई इससे बाहर निकालने की अभी ही आवश्यकता महसूस होती है या संभावना दिखाई देती है?

ध्यान रखिए कि पूर्व की गठबंधन सरकारों की तरह इस सरकार के गठन, मंत्रियों को सरकार में लेने या विभागों के बंटवारे में किसी तरह का खींचतान हमारे सामने नहीं आया। यह अन्य गठबंधन सरकारों से इसे अलग करता है। 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में साथी दलों के 11 मंत्रियों का होना ऐसी संख्या नहीं है जिसे लेकर इस आरोप को स्वीकार कर लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साथी दलों का बहुत ज्यादा दबाव था। दूसरे, विभागों के बंटवारे में भी देखें तो जिन्हें जो मिला उसे लेकर कम से कम सार्वजनिक स्तर पर किसी ने भी अपना असंतोष प्रकट नहीं किया है। ज्यादातर का बयान यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की शीर्ष शक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

गठबंधन सरकारों में साथी दलों के नेता इस तरह बेहिचक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते थे। तीसरे, इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है, शीर्ष मंत्रालयों में फेरबदल न होना। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय , विदेश मंत्रालय यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय, सडक़ परिवहन मंत्रालय आदि उन्हीं वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में है। सरकार गठन के पहले मीडिया में साथी दलों द्वारा अलग–अलग मंत्रालयों के मांग की अटकलें आ रही थी, जिनमें बिहार द्वारा रेल मंत्रालय की मांग शामिल थी।हालांकि इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हुई। कहने का यह अर्थ नहीं कि साथी दलों की अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं और महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप चाहत नहीं होगी और उन्होंने प्रधानमंत्री या अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के समक्ष अपनी बात रखी ही नहीं होगी। आगे भी वह अपनी बात नहीं रखेंगे ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। मूल बात है जिद पर अडऩा और सरकार को मजबूर करके अपने अनुकूल निर्णय बदलवा लेना। उदाहरण के लिए यूपीए सरकार में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रेल मंत्री बने दिनेश त्रिवेदी ने अपने बजट में यात्रियों का जैसे ही किराया बढ़ाया ममता बनर्जी बिफर गई। उन्होंने न केवल बजट में परिवर्तन करने बल्कि रेल मंत्रालय से हटाने का फरमान सुनाया और मनमोहन सरकार को ऐसा ही करना पड़ा। कम से कम वह स्थिति इस समय सरकार में नहीं दिख रही है।

इसी तरह किसी सरकार के नेतृत्वकर्ता की अपनी आभा, देश और काम के प्रति समर्पण तथा उसका दृष्टिकोण व लक्ष्य सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। इस मायने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व अन्य कई प्रधानमंत्रियों से अलग है। साथी दलों में जद (यू) और तेलुगू देशम पहले भी केंद्र और प्रदेश में साथ काम कर चुकी है। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री देश के लिए व्यापक विजन रखते हैं उसमें सभी राज्यों के विकास की उनकी कल्पना है। तो उन्हें नीतियों को लेकर कोई संभ्रम नहीं होगा।

वैसे, आमतौर पर गठबंधन सरकारों में यह मांग होती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी समान न्यूनतम कार्यक्रम बनाकर आगे काम किया जाए। न राजग के नेताओं ने चुनाव में जाने के पहले ऐसी मांग की और न सरकार गठन के पूर्व। भाजपा को बहुमत न मिलने के बाद उनके पास इसका अवसर था और वैसा कर सकते थे। अगर उन्होंने मांग नहीं किया तो इसका अर्थ यही है कि पूर्व सरकार की ओर से जो एजेंडा रखा गया है उससे वह सहमत हैं। यह भी ध्यान रखिए कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में अपने हिंदुत्व व राष्ट्रवाद संबंधी एजेंडा पर खुलकर काम किया है और शेष कार्यों के लिए उन्होंने घोषणाएं भी की है। इस समय भविष्य की तस्वीर के बारे में निश्चिंतता के साथ पूरी तरह भविष्य की तस्वीर बनाने की बजाय हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हां , इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पूर्व की गठबंधन सरकारों से वर्तमान मोदी गठबंधन सरकार अपने चरित्र, आंतरिक संरचना व सामूहिक मनोविज्ञान आदि के स्तर पर काफी हद तक अलग है।

पेड़ बचाओ—पेड़ लगाओ

विनीत नारायण

पूरी दुनिया भीषण गर्मी से झुलस रही है। हजारों लोग गर्मी की मार से बेहाल हो कर मर चुके हैं। दुनिया के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है, कि पेड़ बचाओ–पेड़ लगाओ। क्योंकि पेड़ ही गर्मी की मार से बचा सकते हैं।

ये हवा में नमी को बढ़ाते हैं और मेघों को आकर्षित करते हैं, जिससे वष्रा होती है। आप दो करोड़ की कार को जब पार्किंग में खड़ा करते हैं तो किसी पेड़ की छांव ढूंढ़ते हैं। क्योंकि बिना छांव के खड़ी आपकी कार दस मिनट में भट्टी की तरह तपने लगती है। इस बार हज में जो एक हजार से ज्यादा लोग अब तक गर्मी से मरे हैं, वे शायद न मरते अगर उन्हें पेड़ों की छाया नसीब हो जाती।

चलो वहां तो रेगिस्तान है पर भारत तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम वाला देश है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों, साहित्य और इतिहास में ही नहीं चित्रकारी और मूर्तिकला में भी परिलक्षित होता है। पर दुर्भाग्य देखिए कि आज भारत भूमि तेजी से वृक्षविहीन हो रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत का हरित आवरण भूभाग का कुल 24.56 प्रतिशत ही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत आप खुद जानते हैं। अगर हवाई जहाज से आप भारत के ऊपर उड़ें तो आपको सैकड़ों मीलों तक धूल भरी आंधियां और सूखी जमीन नजर आती है। पर्यावरण की दृष्टि से कुल भूभाग का 34 फीसद अगर हरित आवरण हो तो हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है।

भवन निर्माताओं की अंधी दौड़, बढ़ता शहरीकरण और औद्योगीकरण, आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बड़ी–बड़ी परियोजनाएं, जंगलों के कटान के लिए जिम्मेदार हैं। मानवशास्त्र विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि पर्यावरण की सुरक्षा का सबसे बड़ा काम जनजातीय लोग करते हैं। वे कभी गीले पेड़ नहीं काटते, हमेशा सूखी लकडिय़ां ही चुनते हैं। वृक्षों की पूजा करते हैं। पर जब खान माफिया या बड़ी परियोजना की गिद्धदृष्टि वनों पर पड़ती है तो वन ही नहीं, वन्य जीवन भी कुछ महीनों में नष्ट हो जाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए बने कानून और अदालतें केवल कागजों पर दिखाई देते हैं। सनातन धर्म सदा से प्रकृति की पूजा करता आया है। चिंता की बात यह है कि आज सनातन धर्म के नाम पर ही पर्यावरण का विनाश हो रहा है। समाचार पत्रों से सूचना मिली है कि कांवडिय़ों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 33 हजार वृक्षों को काटा जाएगा। इससे पर्यावरणवादियों को ही नहीं, आम जन को भी बहुत चिंता है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में फैली 111 किलोमीटर लंबी कांवड़ मार्ग परियोजना के लिए 33 हजार से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ों और लगभग 80 हजार पौधों को काटा जाएगा। गौरतलब है कि इस परियोजना में 10 बड़े पुल, 27 छोटे पुल और एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शामिल है और इस परियोजना की लागत 658 करोड़ रु पये होगी। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की योजना ऐसे समय में आई है जब भारत के कई राज्य कई हफ्तों से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। भीषण तापमान ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली है।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहले यूपी सरकार को तीन जिलों में परियोजना के लिए कुल 1,10,000 पेड़–पौधों को काटने की अनुमति देने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित की गई है और एनजीटी ने यूपी सरकार से परियोजना का विस्तृत विवरण मांगा है, जिसमें काटे जाने वाले पेड़ों का विवरण भी शामिल है। हजारों पेड़ों की इस कदर निर्मम कटाई से क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तापमान में वृद्धि जारी रहेगी, बारिश का पैटर्न भी बाधित होगा और हवा और भी जहरीली हो जाएगी। हमें विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। परियोजना की पर्यावरणीय लागत की भरपाई के लिए यूपी सरकार ने ललितपुर जिले में वनीकरण के लिए 222 हेक्टेयर भूमि की चिन्हित की है, जो इस क्षेत्र से, जहां से पेड़ काटे जाएंगे काफी दूर है। क्या यह वनीकरण, कांवड़ यात्रा मार्ग पर शुरू होने जा रही परियोजना की लागत के अनुरूप मुआवजा होगा?कुछ वन्य प्रेमी संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए एक ऑनलाइन याचिका भी दायर की है, जिसे हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। पुरानी कहावत है कि विज्ञान की हर प्रगति प्रकृति के सामने बौनी होती है। प्रकृति एक सीमा तक मानव के अत्याचारों को सहती है पर जब उसकी सहनशीलता का अतिक्रमण हो जाता है तो वह अपना रौद्र रूप दिखा देती है।

समर्थन मूल्य बढ़ाना ही काफी नही, खरीद भी हो

अशोक शर्मा

केंद्र सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का जो फैसला किया है, उसे किसानों के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है। देश के किसानों के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है। इसलिए उन्हें हर तरह की मदद की जरूरत है। किसानों का उत्साह बना रहना चाहिए। कृषि एकमात्र ऐसा पेशा है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति रूठ गई तो समझो किसान की किस्मत रूठ गई। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी–तूफान, पाला व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जितने भी रूप हैं, उन पर किसी का भी बस नहीं है। मौसम साथ न दे तो किसान की मेहनत और उसके द्वारा लगाया गया धन बर्बाद होते देर नहीं लगती।

किसानों के लिए पिछले कुछ समय की प्रतिकूलता प्रकृति से संबद्ध तो रही है, कुछ कारण सरकारों से उनकी उम्मीदों से भी जुड़े हैं। देश के कुछ हिस्सों में किसानों का लम्बा आंदोलन भी इन्हीं उम्मीदों से जुड़ा रहा है। पैदावार का उचित दाम न मिलने या फसल की बर्बादी और कर्ज से घिर जाने पर आत्महत्या करने को मजबूर किसानों की डरावनी तस्वीरें भी सामने आती रही है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। इस बढ़ोतरी से किसानों की झोली में दो लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आने की बात कही जा रही है। यह बड़ी रकम है, जो किसानों को संबल देने में सक्षम है।

यह बात दूसरी है कि कृषि क्षेत्र से ऐसी आवाजें भी आ रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की गई है वह ह्यऊंट के मुंह में जीरेह्ल के बराबर है और इससे किसानों को खास लाभ नहीं होगा। सरकार का कहना है कि उसने खुले दिल से मदद की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार की वृद्धि पिछले दस वर्ष में सर्वाधिक है। हालांकि देश के अन्नदाता को जितनी राहत दी जाए उतनी ही कम है क्योंकि हाड़–तोड़ मेहनत के बाद ही खेतों से पैदावार निकल पाती है। यह भी नहीं मानना चाहिए कि सरकार का काम यहां ही खत्म हो गया है। असल में जिन राज्यों में किसान की पूरी फसल की सरकारी खरीद हो जाती है, उन राज्यों के किसानों को अधिकतम लाभ मिलता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। यह भी उजागर तथ्य है कि गेहूं जैसी कई उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कम हुई है। सरकार खरीद कम करे या फिर नहीं के बराबर करे, व्यापारियों से समर्थन मूल्य जितना भी दाम नहीं मिले तो फिर किसान क्या करेगा? यह बुनियादी सवाल कृषक समुदाय लगातार उठाता रहा है। इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग भी उठ रही है।

फिल्म सरफिरा का पहला गाना मार उड़ी जारी, अक्षय कुमार ने दिखाया आम आदमी का जिद्दी अंदाज

अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म सरफिरा को लेकर कमर कस चुके हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। वहीं, अब सरफिरा का पहला मार उड़ी जारी कर दिया गया है, जिसमें आम आदमी बने अक्षय कुमार का जिद्दी अंदाज देखने को मिल रहा है।

सरफिरा में अक्षय कुमार का किरदार एक ईमानदार शख्स है, जो सिस्टम के खिलाफ जाता है, लेकिन इस सफर में उसके सामने मुश्किलों का एक पहाड़ खड़ा है।अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर सरफिरा के लेटेस्ट ट्रैक की रिलीज की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दिल है ये बावरा, लडऩे से कब डरता हैज्। उन्होंने ये भी लिखा, जब जिंदगी कोई चुनौती देती है, तो बस उसकी आंखों में देखो और मार उड़ी!! गाना रिलीज हो गया है। अब सरफिरा होने का वक्त आ गया है। 12 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है।

सरफिरा के गाने मार उड़ी की शुरुआत अक्षय को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के एक साइंस इवेंट से बाहर निकाले जाने से होती है, जबकि वो विनती कर रहे होते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में परेश रावल की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं, एविएशन का बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है।मार उड़ी में एक सीन फ्लैश बैक का भी दिखाया जाता है, जिसमें अक्षय कुमार भारी भीड़ के साथ विरोध करते हुए दिखते हैं। जैसे–जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, अक्षय का किरदार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता हुआ दिखाई देता है।

बॉक्स ऑफिसः मुंज्या का बेहतरीन प्रदर्शन जारी, अब कल्कि 2898 एडी से होगा सामना

मोना सिंह, शरवरी वाघ और अभय वर्मा की फिल्म मुंज्या का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन शुरुआत से जारी है।यह फिल्म का सिनेमाघरों में रिलीज का तीसरा सप्ताह चल रहा है और यह दर्शकों के बीच पकड़ मजबूत बनाए हुए है।जहां दुनियाभर में इसने 100 करोड़ रुपये का आकंड़ा पार कर लिया है, वहीं धीरे–धीरे यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ की ओर बढ़ रही है।आइए जानते हैं मुंज्या ने 20वें दिन कितने रुपये कमाए।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंज्या ने अपनी रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार 2.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 89.95 करोड़ रुपये हो गया है।हॉरर के साथ कॉमेडी के तडक़े से भरपूर इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने किया है।

भारतीय महिलाओं ने दूसरे दिन भी रचा इतिहास, विमेंस टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। दूसरे दिन स्टंप तक साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 236 रन है। इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 603 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। यह विमेंस टेस्ट की एक पारी का सबसे बड़ा स्कोर है।

शेफाली वर्मा ने लगाया था दोहरा शतक

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट खोकर 525 रन बनाए थे। शेफाली वर्मा ने 197 गेंदों पर 205 रन और स्मृति मंधाना ने 161 गेंदों पर 149 रन बनाए थे। साथ ही जेमिमा रोड्रिगेज ने 55 रन की पारी खेली थी। दूसरे दिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 69 रन और ऋचा घोष ने 86 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 2 रन बनाकर नाबाद रहीं।

लौरा वोल्वार्ड्ट ने बनाए 20 रन

पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत औसत रही। 33 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 36 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली। स्नेहा राणा ने उन्हें बोल्ड किया। इसके बाद एनेके बॉश ने 73 गेंदों पर 39 रन बनाए। स्नेहा राणा ने ही उन्हें पवेलियन भेजा। सुने लुस के रूप में टीम को तीसरा झटका लगा। उन्होंने 65 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने भारत को तीसरी सफलात दिलाई। इसके बाद स्नेहा ने डेल्मी टकर का विकेट चटकाया। वह खाता तक नहीं खोल सकीं।

अल्लारी नरेश की फिल्म बच्चला मल्ली का पहला लुक सामने आया

हीरो अल्लारी नरेश अपनी आगामी फिल्म बच्चला मल्ली में एक गंभीर भूमिका में रोमांचित करने के लिए तैयार हैं, जिसका निर्देशन सोलो ब्रैथुके सो बेटर फेम सुब्बू मंगादेवी कर रहे हैं। रज़ेश डांडा और बालाजी गुट्टा इस फिल्म का निर्माण हास्य मूवीज़ के बैनर तले कर रहे हैं, जिसने ब्लॉकबस्टर समाजवरगमना और ऊरू पेरू भैरवकोना जैसी फ़िल्में दी हैं। निर्माताओं ने आज फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया।

अल्लारी नरेश अस्त–व्यस्त बालों और असमान दाढ़ी के साथ पहले कभी न देखे गए सामूहिक अवतार में दिखाई दे रहे हैं। रिक्शा पर बैठे और सिगरेट पीते हुए, नरेश अपनी आँखों में तीव्रता के साथ एक गंभीर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने गले और हाथ में पवित्र धागे पहने हुए हैं। पृष्ठभूमि में, हम आतिशबाजी के साथ एक कार्निवल देख सकते हैं और लोग क्रूर देवताओं की वेशभूषा में हैं। हाई–वोल्टेज फाइट सीक्वेंस का यह आकर्षक पहला पोस्टर दर्शाता है कि बच्चला मल्ली एक गहन और अपनी तरह की पहली एक्शन एंटरटेनर होगी। फिल्म में अमृता अय्यर मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं, जबकि उनके अपोजिट अल्लारी नरेश हैं। रोहिणी, राव रमेश, अच्युत कुमार, बालगाम जयराम, हरि तेजा, प्रवीण, विवा हर्ष आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बड़े पैमाने पर बनने वाली बच्चला मल्ली में कुछ मशहूर तकनीशियन अलग–अलग विभागों को संभालेंगे। सीता रामम से मशहूर हुए विशाल चंद्रशेखर संगीत देंगे, जबकि रिचर्ड एम नाथन जिन्होंने मनाडु, रंगम और मट्टी कुश्ती जैसी फिल्मों में काम किया है, कैमरा संभालेंगे। छोटा के प्रसाद संपादक हैं और ब्रह्मा कदली प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। जबकि कहानी और संवाद सुब्बू ने खुद लिखे हैं, विपार्थी मधु ने पटकथा लिखी है और अतिरिक्त पटकथा विश्वनेत्र ने लिखी है।

डूंगरपुर बना वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग का पहला चैंपियन

उदयपुर (राजस्थान) : पिछले 10 दिनों से वंडर सीमेंट्स क्रिकेट एकेडमी के शिकारबाड़ी क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग के घमासान का आज धमाकेदार समापन हुआ। यूडीसीए के सानिध्य में 100 स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित इस लीग के कांटेदार फाइनल में डूंगरपुर ड्रैगन्स ने रॉयल राजपूताना कॉन्करर्स पर 1 रन से शानदार जीत दर्ज की।

कोहान कोठारी ने बनाए 41 रन

शाम 5 बजे से शुरू हुए इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम का हिस्सा रहे दीपक हुड्डा ने हरी झंडी दिखा कर की। रॉयल राजपूताना कॉन्करर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। वहीं डूंगरपुर की तरफ से पहली गेंद खेलने उतरे कोहान कोठारी ने 27 गेंदों में 41 रन बनाकर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। टीम को पहला झटका 25 रन पर रोहन के रूप में लगा।

टीम ने बनाए 155 रन

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान निखिल सचदेव ने कप्तानी के अनुरूप ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 20 गेंदों में 31 रन ठोंक दिए। उसके बाद अशोक शर्मा की 200 के स्ट्राइक रेट से खेली गई 10 गेंदों पर 20 रन की तेज पारी ने टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 155 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। रॉयल राजपूताना की तरफ से शाबाज खान और करन सिंह ने क्रमशः 2–2 विकेट झटके।

मलबे की चपेट में आने से खाई में गिरी मैक्स, चार घायल, एक लापता

● शनिवार दोपहर कोटद्वार से सवारी लेकर पौड़ी जा रहा था मैक्स वाहन ● राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए मलबे को हटाकर लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी टीम

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसाती रपटे के समीप पहाड़ी से आए भारी मलबे की चपेट में आने से एक मैक्स वाहन खाई में गिर गया। दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए। जबकि, मैक्स सवार एक व्यक्ति लापता हो गया। प्रशासन, एसडीआरएफ व पुलिस की टीम जेसीबी व पोकलेंड मशीन से मलबा हटाकर लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी रही। वहीं, हाईवे पर मलबे के कारण करीब तीन घंटें तक लंबा जाम लगा रहा।

घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है। पौड़ी पैडुल गांव निवासी मुकेश गुसाईं कोटद्वार से सवारी लेकर पौड़ी के लिए रवाना हुआ। वाहन में मुकेश सहित नौ सवारियां थी। जैसे ही मैक्स वाहन कोटद्वार से करीब सात किलोमीटर दूर बरसाती रपटे के पास पहुंचा। अचानक एक बड़ा पत्थर गाड़ी के समीप गिरा। चालक मुकेश ने जैसे ही पहाड़ी से भारी मलबा आते हुए देखा तो उसने तुरंत सवारियों को मैक्स से निकलने के लिए कहा और खुद भी मैक्स को छोड़कर भागने लगा। इसी दौरान भारी मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा और मैक्स वाहन को अपने साथ खाई में बहाकर ले गया। घटना की जानकारी मिले ही तहसील प्रशासन, पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और चालक मुकेश के साथ ही मुरादाबाद निवासी सकिल (55 वर्ष) पुत्र शौकीन, चंद्रवीर सिंह (53) वर्ष पुत्र ओमपाल सिंह व ग्राम गहड़ बुआखाल निवासी संजय नेगी (31) पुत्र सते सिंह को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया। जबकि, दुर्घटना में चार अन्य सवारियों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। घायल मैक्स सवार लोगों ने बताया कि वाहन में मुदाराबाद निवासी असलम (58 वर्ष) भी मौजूद था। मलबा गिरने से पहले वह भाग पाता उससे पहले ही वह मैक्स के साथ खाई में गिर गया।

कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया भारी मलबा

कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य मलबा आने के बाद यातायात खुलने का इंतजार करते वाहन चालक व यात्री

उफान पर बनी रही नदियां

शनिवार को हुई बारिश के दौरान क्षेत्र की अधिकांश नदियां उफान पर बनी हुई थी। क्षेत्र के सभी नालों व गदेरों में भी अचानक पानी बढ़ गया। ऐसे में वर्षाकाल की पहली बारिश ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जबकि, गत वर्षा काल में वर्षा के दौरान भारी तबाही मची थी। गाड़ीघाट क्षेत्र में खोह नदी अपने साथ कई आवास बहाकर ले गई थी।

एक नजर

बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर किया मंथन

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : शनिवार को बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर स्थानांतरण समिति की बैठक एडीएम की अध्यक्षता में पौड़ी में आयोजित हुई। तबादलों की जद में आने वाले शिक्षकों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी को आपत्ति होगी तो उनका निराकरण होगा। जिले में विभिन्न श्रेणियों में करीब पांच सौ से अधिक शिक्षकों के तबादले किए जाने हैं।

बैठक के बाद एडीएम पौड़ी ईला गिरी ने बताया कि जिले में बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस सत्र में ट्रांसफर होने वाले विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के तबादलों को लेकर सूचना पोर्टल पर डाली जाएगी। इसके बाद यदि किसी को आपत्ति होगी तो उनका निराकरण होगा। इसके बाद बेसिक शिक्षकों के तबादलों को लेकर रास्ता भी साफ हो जाएगा। सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम से पत्नी-पति, अनुरोध के आधार और अन्य सभी श्रेणियों के तबादले इसमें शामिल है। पौड़ी के डीईओ बेसिक एवं तबादला समिति के सचिव नागेंद्र बड़थवाल के मुताबिक समिति की बैठक में विभिन्न मसलों पर बिन्दु वार चर्चा हो गई है। बैठक के बाद बेसिक शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया भी जल्द अमल में लाई जाएगी। बैठक में सभी बीईओ भी मौजूद रहे।

खाई में गिरी कार, चालक सहित तीन घायल

नई टिहरी : प्रतापनगर प्रखंड के कोडार दीनगांव मुखेम मोटर मार्ग के किलोमीटर 14 पर शुक्रवार देर रात इको कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में चालक सहित तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चौंड लम्बगांव ले जाया गया। जहां से सभी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रैफर किया गया है।

पुलिस की मीडिया सेल के अनुसार बीती देर शाम को मुखेम से दीनगांव की ओर जाते हुए ईका कार का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। बमुश्किल वाहन में सवार तीनों लोगों को खाई से बाहर निकाला गया। जिसके बाद प्राइवेट वाहन की मदद से घायलों को सीएचसी चौंड में इलाज के लिए लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रैफर किया गया। इस दुर्घटना में चालक 55 वर्षीय गोकुल सिंह पंवार निवासी दिनगांव थाना लम्बगांव, 40 वर्षीय मदन लाल निवासी दिनगांव और 45 वर्षीय सोनपाल निवासी हेरवाल गांव थाना लम्बगांव गंभीर घायल हुए हैं। रेस्क्यू करने में पुलिसकर्मियों में नागेंद्र सिंह, अरविंद , मुकेश रावत, कर्ण सिंह, सचिन आदि शामिल रहे। (एजेंसी)

केवाईसी शिविर लगाने की उठाई मांग

नई टिहरी : ब्लॉक प्रमुख देवप्रयाग सूरज पाठक ने डीएम टिहरी से क्षेत्र के गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी करवाने को हिंडोलाखाल में शिविर लगवाने का अनुरोध किया है।

डीएम टिहरी को भेजे पत्र में ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ब्लॉक के सुदूर गांवों तक चंद्रवदनी गैस एजेंसी, अंजनी सैण की ओर से गैस आपूर्ति की जाती है। इनमें कई गांव 85 किमी. से अधिक दूरी पर हैं। यहां के उपभोक्ताओं को काफी किराया देकर केवाईसी करवाने एजेंसी तक पहुंचना पड़ रहा है। जिनमें अधिकांश उपभोक्ताओं का उसी दिन केवाईसी नहीं हो पाने से उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इससे ब्लॉक के गैस उपभोक्ताओं में लगातार रोष बना है। प्रमुख ने डीएम से सम्बंधित एजेंसी से ब्लॉक मुख्यालय में केवाईसी शिविर लगवाकर गैस उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। (एजेंसी)

प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त

नई टिहरी : बहादराबाद में नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर प्रतापनगर विधायक विक्रम सिह नेगी ने गहरा दुःख और रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहादराबाद की घटना शर्मसार करने वाली है, जिससे देवभूमि कलंकित हुई है। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि प्रदेश में महिला आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी होने से देवभूमि कलंकित हो रही है और देवभूमि उत्तराखंड अपनी पहचान खोता जा रहा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। (एजेंसी)

डीएम ने सीएमओ को लगाई फटकार

मेडिकल स्टोरों का गंभीरता और बारीकी से निरीक्षण करने के दिए निर्देश

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में नार्को कोर्डिनेशन सेंटर समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकाी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को फटकार लगाते हुए सभी मेडिकल स्टोरों का गंभीरता और बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कोटपा अधिनियम-2003 के अन्तर्गत वैधनिक कार्यवाही करने के लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश देते हुए अगली बैठक से पूर्व तक 350 चालान करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने उपजिलाधिकारी कोटद्वार, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा स्थानीय संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिडकुल क्षेत्र कोटद्वार में 01 सप्ताह के भीतर अस्थाई नशामुक्ति केन्द्र का संचालन प्रारंभ करें।

शनिवार को आयोजित बैठक में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में असंतोषजनक कार्यवाही के चलते मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी मेडिकल स्टोरों का गंभीरता से और बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित ड्रग इंसपेक्टर को 07 दिन के लिए युद्धस्तर पर जनपद में निरीक्षण करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं या नहीं, मेडिकल स्टोर संचालक के पास लाइसेंस, संचालक स्वयं तैनात रहता है कि नहीं तथा मेडिकल स्टोर बच्चों को कोई नशीली सामग्री तो नहीं विक्रय करता अथवा कोई अवैध तरीके की नशीली दवाएं तो नहीं बेच रहे हैं इसका बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रुप से स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए वर्कशॉप अथवा जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा।

संगठन की मजबूती का लिया संकल्प

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती का संकल्प लिया है। इस दौरान पूर्व शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारियों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। कांग्रेस महानगर की अध्यक्ष सुधा असवाल व पूर्व प्रदेश महामंत्री रंजना रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जनता के असली मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी ही सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को दरकिनार कर जनता का शोषण करने का कार्य कर रही है। कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित अन्य मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह बिष्ट, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन सिंह गुसाई, बलवीर सिंह रावत, धर्मपाल सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह गुसाईं, सुधा असवाल, चंद्रमोहन असवाल, प्रदीप सिंह नेगी, विजय नेगी, अनस गबर सिंह रावत, कृपाल सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

पहली बारिश में दगा दे गया राष्ट्रीय राजमार्ग, मलबे ने लगाया यातायात पर ब्रेक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : बरसात की पहली बारिश में ही कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग ने धोखा दे दिया है। हालत यह है कि शनिवार को बारिश के कारण जगह-जगह मलबा आ गया। जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बनी हुई थी। अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही लोग घंटों मलबा हटने का इंतजार करते रहे।

बीते वर्ष बरसात में कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बदहाल हो गया था। जगह-जगह बोल्डर गिरने व पुश्ते ढहने से राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिन तक बंद रहा। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जेसीबी व पोकलेंड मशीनों से बोल्डर हटवाकर यातायात को सुचारु करवाया। इसके बाद भी कोटद्वार से दुगड्डा तक 15 किलोमीटर के सफर में दस से अधिक डेंजर जोन बने हुए थे। होना तो यह चाहिए था कि वर्षा थमने के बाद सरकारी सिस्टम इन डेंजर जोन की मरम्मत करवाता। लेकिन, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारी सिस्टम ने इसकी सुध नहीं ली। नतीजा गत वर्षाकाल के जख्म इस वर्ष भी भारी पड़ रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश के दौरान कोटद्वार से सात किलोमीटर दूर बरसाती रपटा ऊफान पर आ गया। वाहन चालक घंटों रपटे का पानी कम होने का इंतजार करते थे। वहीं, दुर्गा मंदिर के समीप पहाड़ी से भारी मात्र में बोल्डर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। हालांकि, मौके पर खड़ी जेसीबी मशीन लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी हुई थी। वहीं, कई स्थानों पर पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का भी डर बना हुआ था।

कोटद्वार दुगड्डा के मध्य डेंजर जोन में गुजरते वाहन

पौड़ी की पूर्व एसएसपी श्वेता चौबे को किया सम्मानित

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : जागृति गढ़वाल जनजागरण संस्था की ओर संचालित रेडियो गढ़वाणी की ओर से पौड़ी जिले की पूर्व पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे को सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति ने उनके कार्यों की भी प्रशंसा की। कहा कि पौड़ी जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में श्वेता चौबे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संस्था के सदस्यों ने देहरादून पहुंच कर जनपद पौड़ी की पूर्व एसएसपी श्वेता चौबे स्मृति चिह्न व शाल ओढ़ा कर को सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष मनीष भट्ट ने कहा कि पौड़ी जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए श्वेता चौबे ने अपराध को रोकने के लिए बेहतर कार्य किया। कहा कि कोटद्वार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। जिससे यहां लगातार आपराधिक घटनाओं का अंदेशा बना रहता था। शहर में लगातार चोरी व अन्य घटनाएं होती रहती थी। ऐसे में तत्कालीन एसएसपी श्वेता चौबे ने बार्डर के साथ ही शहर में जगह–जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध पर विराम लगाने का प्रयास किया। आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए भी उन्होंने कई अभियान चलाए। इस मौके पर समृद्ध नेगी, रोहित रावत, निर्मला नेगी, जागृति आदि मौजूद रहे।

पौड़ी की पूर्व एसएसपी को सम्मानित करते सदस्य

शादी की 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई

ढोल-दमो और मशकबीन की धुन पर झूमें लोग

जयन्त प्रतिनिधि।

सतपुली : शादी की 25वीं और 50वीं सालगिरह को अब भव्यता के साथ मनाने का ट्रेंड धीरे-धीरे शहर से लकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इसे मनाया पहले भी जाता रहा है लेकिन अब इसे पारिवारिक समारोह से निकालकर एक बड़े समारोह में तब्दील किया जा रहा है। पोखड़ा ब्लॉक के सेवानिवृत्त पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य ग्राम जिनोरा निवासी राम रतन सिंह कंडारी की शादी की 50वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया।

इस दौरान सभी रिश्तेदार ढोल-दमो और मशकबीन की धुन पर नृत्य कर झूम उठे। रात्रि भोज के पश्चात पूर्वजों के समय में प्रचलित जोकर नृत्य के कलाकार श्याम लाल एवं टीम द्वारा प्रस्तुति देकर विलुप्त हो रही संस्कृति को संजोने का भी प्रयास किया गया।

इस स्वर्णिम वर्षगांठ के आयोजन को उनके बेटों, बेटियों और नाती पोतों द्वारा गुप्त रखा गया। शुक्रवार सुबह जब घर पर टेंट, हलवाई, पारंपरिक वाद्ययंत्र ढोल-दमो, मशकबीन के साथ-साथ सगे संबधी और रिश्तेदार आने लगे तो वे अचंभित रह गये। कार्यक्रम की परिकल्पना उनके बेटे बहु जसवंत और कल्पना द्वारा की गई, जिसमे उनके अन्य बेटे-बहू बसंत-कांती, हेमंत-नीलम, कृष्णा-आरती और बेटी दामाद किरन-धर्मवीर व मीरा-दीपक तथा सभी नाती पोतियों ने सहयोग कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिये। कार्यक्रम की शुरूआत प्रातः श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा के साथ भजन कीर्तन से हुई। शाम ढलते ही रिंग सेरेमनी और जय माला के बाद केक काटा गया। बड़े दामाद धर्मवीर सिंह द्वारा उनके 50 वर्ष के स्वर्णिम सफर का वंश वृक्ष का चित्र भेंट किया गया।

आस्ट्रेलिया की कैनबरा विवि के छात्र करेगें गढ़वाल विवि का भ्रमण

जयन्त प्रतिनिधि। श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बेहतरीन शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धियां अब अंतरराष्ट्रीय विवि में भी देखने को मिल रही है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालय में से आस्ट्रेलिया की 10 टाप विश्वविद्यालय में शुमार कैनबरा विश्वविद्यालय ने अपने छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण के लिए गढ़वाल विवि का चयन किया है। कैनबरा विवि के छात्र 5 नवम्बर से 23 नवम्बर तक गढ़वाल विवि का भ्रमण करेंगे। आगामी 5 नवम्बर 2024 से शुरू होने शैक्षणिक भ्रमण को लेकर कैनबरा विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र के छात्र-छात्राएं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत कैनबरा विवि के चयनित छात्र-छात्राएं गढ़वाल विवि के शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानेगें। बताते चले कि बीते सितंबर माह में कैनबरा विश्वविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर रीना घिल्डियाल ने गढ़वाल विवि का भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल विवि के शैक्षणिक गतिविधियों और शोध कार्यो के बारें में जानकारी जुटाई। गढ़वाल विवि में हो रहें शोध कार्यो और शैक्षणिक गतिविधियों से संतुष्ट होकर कैनबरा विवि ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किये गये। एमओयू में शैक्षणिक भ्रमण में कैनबरा विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस और बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेज में नामांकित होने वाले छात्र-छात्राओं को हिमालय में विज्ञान अध्ययन यात्रा का अध्ययन कर अपनी-अपनी डिग्री में 3 अकादमिक क्रेडिट अंक अर्जित करने होगें।

भारी वाहनों के लिए लागू हुई नो इंट्री

जयन्त प्रतिनिधि।पौड़ी : जिला मुख्यालय में शनिवार से भारी वाहनों के लिए नो इंट्री लागू हो गई। अब भारी वाहन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक शहर की सड़कों नहीं चल सकेंगे। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। अक्सर देखा गया है कि हादसें के बाद ही प्रशासन नींद से जागता है। शनिवार को सुबह से ही मुख्यालय की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं देखी गई। शुक्रवार को पौड़ी-कोटद्वार नेशनल हाईवे पर डंपर की चपेट में आने से एक युवती की भी मौत हो गई थी। इसके बाद हरकत में आए पुलिस विभाग ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर यह रोक लगा दी। इसके लिए शहर के बाहर ही तीन स्थानों पर बैरियर लगाए गए है। वहीं सड़क किनारे रखी भवन सामग्री को भी तत्काल हटाने की हिदायत पुलिस ने दी है।

मैदान को वापस लौट रहे प्रवासी, वाहनों की मारामारी

दिल्ली, गुरुग्राम सहित अन्य रूटों पर बढ़ी यात्रियों की संख्या

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : एक माह पूर्व गर्मियों की छुट्टी पर गांव आए प्रवासियों के वापस लौटने का दौर शुरू हो गया है। यहीं कारण है कि अचानक मैदानी क्षेत्रों को संचालित होने वाले वाहनों पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली, गुरुग्राम सहित अन्य रूटों पर वाहन पकड़ने के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों की संख्या को देखते हुए रूटों पर अतिरिक्त बसों का भी संचालिन किया जा रहा है।

स्कूलों की छुट्टी पड़ने के बाद मैदान से सैकड़ों प्रवासी अपने गांव आए हुए थे। लेकिन, अब एक जुलाई से अधिकांश स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में अब प्रवासी गांव से वापस मैदान की ओर लौट रहे हैं। नतीजा, पहाड़ से कोटद्वार पहुंच रही जीएमओयू व मैक्स वाहन भी यात्रियों से पूरी तरह भरे हुए थे। कोटद्वार स्टेशन में उतरते ही मैदानी रूट पर जाने वाली बस में सीट के लिए मारामारी मची हुई थी। कई यात्री बस की खिड़कियों से सामान डालकर सीट घेरने के प्रसार में जुटे हुए थे। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों को हो रही थी। हालांकि रोडवेज की ओर से यात्रियों की संख्या को देखते हुए रूट पर वाहनों का संचालन करवाया जा रहा था।

कोटद्वार बस स्टेशन में दिल्ली के लिए बस के इंतजार में खड़े यात्री

योजनाओं के नीतिगत निर्णयों हेतु शुद्ध आंकड़े महत्वपूर्ण

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डेय की उपस्थिति में 18वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया गया। महान सांख्यिकी विद् एवं वैज्ञानिक प्रो. प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार स्तर से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हेतु प्रतिवर्ष अलग-अलग थीम निर्धारित की जाती है। इस वर्ष की थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग तय की गई है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न सामाजार्थिक विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के नीतिगत निर्णयों हेतु शुद्ध आंकड़ों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने फील्ड स्तर से सर्वेक्षणों से आंकड़ों के संग्रहण, संकलन व विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त किये जाने हेतु आधुनिक सांख्यिकी टूल्स का प्रयोग करने तथा इस पूरी प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने ने अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण एवं तद्जनित रिपोट्र्स के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीतिगत निर्णयों के आगत के रूप में उपयोगी हैं। इस दौरान सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी वी.एस. नेगी, राजेंद्र कुमार सहित मंगलमोहन, दिगम्बर सिंह व विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।

युवा वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रकाशित करने के मिलेंगे अवसर

देहरादून। यूनिवर्सिटीज जर्नल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री एंड आयुर्वेदिक हाइट्स (उजपा) ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के साथ शुक्रवार को संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटीज जर्नल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री एंड आयुर्वेदिक हाइट्स पत्रिका का विमोचन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इसमें युवा वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रकाशित करने के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत उजपा के मुख्य संपादक डॉ एस फारूक ने किया। सहयोगी संपादक डॉ हिम्मत सिंह ने पत्रिका का परिचय दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटीज जर्नल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री एंड आयुर्वेदिक हाइट्स का विमोचन हुआ। इका उद्देश्य युवा और उभरते वैज्ञानिकों को उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रकाशित करने के अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करना है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी ने आयुर्वेद की आवश्यकता पर जोर दिया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजीव मोहन पंत ने जड़ी बूटियों के शोषण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पत्रिका हर्बल अनुसंधान की सफलता की कहानियों को प्रतिबिंबित करेगी।

वेतन वृद्धि और विभाग में समायोजित किया जाय

श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ का प्रतिनिधि शिष्टमंडल वेतन वृद्धि सहित विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर शनिवार को जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक से मिला। इस दौरान शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहें जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के प्रदेश महामंत्री मंगलेश लखेड़ा ने वेतन वृद्धि सहित विभाग में समायोजित करने की मांग मुख्य महाप्रबंधक के सम्मुख रखी। मंगलेश लखेड़ा ने बताया कि मांगों पर मुख्य महाप्रबंधक ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इस मौके पर चंद्रमोहन खत्री, गोविंद आर्य, गिरीश चंद्र, गणेश नाथ, सुरजीत डोबरियाल, देवाकिशोर कंडवाल सहित आदि मौजूद थे।

अवैध खनन की गतिविधि पर पूर्ण विराम लगाये : डीएम

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को संबंधित खनन क्षेत्रों में किसी भी तरह के अवैध खनन की गतिविधि पर पूर्ण विराम लगाने के निर्देश दिये।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने विभागीय राजस्व वसूली की प्रगति बढ़ाने के लिए प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के राजस्व वसूली के अंतर्गत गत वर्ष और इस वर्ष के दोनों आंकड़ों तथा तारगेट और उसकी पूर्ति के आंकड़ों दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा, जिससे यदि किसी विभाग की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस दौरान वर्चुअल बैठक में आबकारी, पुलिस, रजिस्ट्रार, राजस्व, वन विभाग, खनन, पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

एक नजर

प्रत्येक घर में आपदा किट होना जरूरी

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : श्री रंवि रंजन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में शनिवार को पुलिस लाईन रतुडा जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबन्धन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग की आपदा प्रबन्धन ईकाई के उपनिरीक्षक भगत सिंह के द्वारा पीएलवी गणों को आपदा के समय आपदा में लाये जाने वाले गुर एवं तकनीकी जानकारी दी गयी। साथ ही बताया कि वर्तमान समय में प्रत्येक घर में आपदा किट होना चाहिए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्रीमती यशोदा खत्री, भूपेश जोशी, कमलेश नेगी, एस.डी.आर.एफ. के जवान व महिलाएं उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप का दून में प्रदर्शन

देहरादून।दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर ईडी एवं सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शनिवार सुबह गांधी पार्क पर प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी एवं सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जांच एजेंसियों से झूठे मामले बनवाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नही हैं कि सड़क पर कोई जनहित के मुद्दे उठाए तो उस पर सरकार रासुका लगाकर जेल भेज देती हैं। संसद में आवाज उठाई जाए तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। कहा कि इस तरह परेशान किया गया तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

निवेश के नाम पर 90 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

देहरादून। एसटीएफ ने निवेश के नाम पर नैनीताल निवासी व्यक्ति से 90 लाख की ठगी के आरोपी को शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नैनीताल निवासी एक व्यक्ति ने 18 जून 2024 को केस दर्ज कराया गया था। उसने बताया था कि उसे एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से से जुड़ा गया था। ग्रुप के माध्यम से निवेश से काफी रुपये कमाने का लालच देकर और एक एप डालनलोड कराई गई। एप के माध्यम से उनसे करीब 90 लाख रुपये निवेश कराए गए।

बताया कि कुछ ही दिनों में उनके डेसबोर्ड पर 90 लाख रुपये की धनराशि मुनाफे के साथ दो करोड़ रुपये दिखने लगी। साइबर क्राइम पुलिस ने घटना में बैंक खातों, मोबाइल नंबर, जीमेल और व्हाट्सएप की जानकारी जुटाई। पता चला कि अपराधियों ने दूसरे व्यक्तियों के नाम से आवंटित मोबाइल सिम, बैंक खातों का प्रयोग किया। दिल्ली, गुजरात, कॉलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के बैंक खातों में धोखाधड़ी की रकम भेजी गई।

एसएसपी ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को बागपत यूपी निवासी एक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक मोबाइल, छह चैक बुक, छह पासबुक, बैंक चैक, छह डेबिट कार्ड, विभिन्न कम्पनी के 33 सिम कार्ड, फर्जी मुहर आदि बरामद हुए हैं।

एलजीबीटीक्यू समुदाय की प्राइड परेड आज

देहरादून। एलजीबीटीक्यू समुदाय की ओर से रविवार को शहर में प्राइड परेड निकाली जाएगी। परेड के माध्यम से समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। शनिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में समुदाय की ओसीन ने बताया कि एलजीबीओक्यू समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। बावजूद इसके सदस्यों को समाज में स्वीकार्यता और समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने इस समुदाय के लोगों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए।

युवती ने मुनाफे के लालच में गंवाए 1.99 लाख

देहरादून। दून निवासी एक युवती ने ऑनलाइन निवेश से मुनाफ कमाने के लालच में 1.99 लाख रुपये गंवा दिए। युवती ने शुक्रवार को राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष पीडी भट्ट के अनुसार उन्होंने तहरीर में बताया कि 10 जून को कुछ लोगों ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़ा था। गुप के माध्यम से शुरू में उन्हें एक यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाने का टास्क दिया गया।

अवैध खनन पर लगाएं पूर्ण रोक : डीएम

डीएम ने ली जिला खनन निरोधक समिति की बैठक

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को जिला खनन निरोधक समिति की बैठक लेते हुए सभी एसडीएम, पुलिस, परिवहन और खान अधिकारियों को जनपद में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिए। खनिज भंडारण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की अवशेष धनराशि की वसूली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिले में नए खनन चुगान क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए। ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ राजस्व को बढ़ाया जा सके। एसडीएम और पुलिस विभाग सामाजस्य बनाकर अवैध खनन में सीज वाहनों को रखने की व्यवस्था भी करें। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध खनन की रोकथाम और खनन मामलों में आरोपित अर्थदंड की वसूली के लिए तहसील स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन ने बताया कि खनन निरोध दल ने 01 अप्रैल 2023 से अब तक 65 अवैध खनन के प्रकरणों में चालान की कार्रवाई करते हुए 81.18 लाख का अर्थदंड लगाया है। जिसमें से 32.50 लाख धनराशि जमा कर दी गई है। जबकि 48.68 लाख धनराशि अवशेष है। जिला खनन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के प्रकरणों में 07 मार्च 2024 से पूर्व आरोपित धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का दो गुना की धनराशि आरोपित कर ऐसे प्रकरणों का एकमुश्त समाधान योजना के तहत किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण हेतु दो माह का समय निर्धारित है। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिए जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित संपूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य है। बैठक में उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, खनन अधिकारी नाजिया हसन सहित वर्चुअल माध्यम से तहसीलों से सभी उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक किशोर ने अफसरों के साथ किया बांस का रोपण

नई टिहरी : विकासखंड चंबा के देवरी मल्ली में मनरेगा एवं एनआरएलएम के अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा, जल संरक्षण एवं संवर्धन को विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय और अधिकारियों ने बायो फेंसिंग बांस की सघन रोपाई की। इस मौके पर जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए ग्रामीणों के बीच कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें प्रेरित करने का काम किया गया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने विभागीय अधिकारियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए कहा कि डीएम दीक्षित के मार्गदर्शन एवं सीडीओ के संरक्षण में देवरी मल्ली में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भूमि संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा, वॉटर रिचार्ज के साथ ही आय के स्त्रोत विकसित करने होंगे। देवरी मल्ली पूरे प्रदेश में एक आदर्श गांव बने इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर एवं गांववासियों के सहयोग से ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी के स्त्रोत सूख रहे हैं या पानी में कमी रहती है, को चिन्ह्ति कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए एकीकृत योजना के साथ जल संरक्षण एवं संवर्धन करें। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा महिलाओं के बोझ को कम करना तथा प्रत्येक महिला को लखपति बनाना है। इस मौके पर सीडीओ डा. अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि बांस की सघन रोपाई से भविष्य में जल, जंगलों की सुरक्षा और आजीविका संवर्धन के अवसर तो प्राप्त होंगे। खेती-बाड़ी की जंगली जानवरों से सुरक्षा भी होगी।

उन्होंने कहा कि देवरी मल्ली में अच्छी कृषि भूमि है, यहां पर रोजगार परक कार्य हो सके, इसके लिए खेतों में बुवाई कराई गई है और जंगली जानवरों से खेती-बाड़ी की सुरक्षा हेतु ग्राम वासियों के सहयोग से खेतों की मेढ़ों पर डेढ़ किलोमीटर के पैच में एक हजार बांस का पौधरोपण किया गया है।

सांख्यिकी दिवस पर महालनोबिस को किया याद

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : अर्थ एवं संख्या विभाग में शनिवार को सांख्यिकी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारत में सांख्यिकी विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया।

जिला अर्थ एवं संख्या कार्यालय में निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सतत विकास लक्ष्यों पर विचार विमर्श के सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने पीसी महालनोबिस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी ओर से किये गये कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्य, उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह सहित सभी कर्मचारी मौजूद थे।

हेलीपैड परियोजना के कार्यों को तेजी से करें पूरा : डीएम

एसडीएम निर्माणाधीन हेलीपैड कार्यों की मॉनिटरिंग करें

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को जनपद में हेलीपैड निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि हेलीपैड निर्माण कार्यों के लंबित प्रकरणों का तत्काल समाधान करते हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्रों में निर्माणधीन हेलीपैड कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करें। जिन हेलीपैड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए।

जिलाधिकारी ने भू-वैज्ञानिक अधिकारी को एसडीएम से समन्वय करते हुए गोविंदघाट, घांघरिया और औली में हेलीपैड निर्माण हेतु स्थल चयन करने के निर्देश दिए। थराली एसडीएम को कुलसारी में निर्माणाधीन हेलीपैड निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए जनपद में नए हेलीपैड निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करें। स्थान चिन्हित करते हुए सड़क से कनेक्टिविटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में बताया गया कि जनपद में 11 हेलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसमें से हेमकुंड साहिब, कोठियालसैंण और कुलसारी में निर्माण कार्य चल रहा है। सिंहधार, घांघरिया, वाण, रविग्राम औली, गोविन्द घाट, वेदनी में हेलीपैड निर्माण और भराडीसैंण में हेलीपैड विस्तारीकरण के कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में चल रहे है। बैठक में उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, वन विभाग के एसडीओ जुगल किशोर, ग्रामीण विकास विभाग के अधिशासी अभियंता अला दिया, लोनिवि के सहायक अभियंता सचिन अशोक सहित वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम और संबधित अधिकारी उपस्थित थे।

उप चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा के 105 बूथों से होगी वेबकास्टिंग

वेबकास्टिंग के लिए कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : बद्रीनाथ विधानसभा उप चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विधानसभा के 105 बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी।

शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में रिजर्व सहित 118 वेबकास्टिंग कार्मिकों को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया।

मास्टर ट्रेनर प्रभात रावत ने वेब कास्टिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ मतदेय स्थलों पर कैमरे के इंस्टॉलेशन, संचालन और नेट कनेक्टिविटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नोडल अधिकारी हेमंत मौर्य ने बताया कि मतदान के दिन 105 बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। वेबकास्टिंग के लिए कार्मिकों को 07 जुलाई को रवाना किया जाएगा। वेबकास्टिंग में तैनात कार्मिकों को पोस्टल बैलेट से अपना मतदान करने के लिए 07 जुलाई को ही सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। वेबकास्टिंग की कन्ट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। इन केंद्रों पर मतदान शुरू होने से लेकर मतदान की समाप्ति तक की पल-पल की गतिविधियों पर आयोग की सीधी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 50 फीसदी मतदेय स्थलों पर लाइव निगरानी रखी जाएगी। जहां वेब कास्टिंग होनी है वहां पर विभिन्न चरणों में ट्रायल भी आयोजित किए जाएंगे।

होम वोटिंग : 134 मतदाताओं ने किया मतदान

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : विधानसभा उप निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर 85 प्लस के वृद्ध मतदाता व दिव्यांग मतदाता जो मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की व्यवस्था की है। शनिवार को होम वोटिंग में तैनात मतदान कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर मतदान कराया गया। होम वोटिंग के पहले दिन 134 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बद्रीनाथ विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार 734 वरिष्ठजन व 990 दिव्यांग पंजीकृत हैं, जिनमें से 114 वरिष्ठजनों व 27 दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग का विकल्प चुना था। शनिवार को होम वोटिंग के लिए तैनात 25 पार्टियों ने घर-घर जाकर 27 दिव्यांगजनों एवं 107 वरिष्ठजनों को मतदान कराया। वही 7 वरिष्ठ नागरिक जनपद से बाहर हैं। जो मतदाता आज किसी कारणवश अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए वो 05 जुलाई को वोट कर सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से की मुलाकात

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भेंट कर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की बधाई और शुभकामनाएं दी।इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने ओम बिड़ला को 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में चुने जाने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा की यह ऐतिहासित क्षण है। वह दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा में उनकी अध्यक्षता में कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए जिन्हें सदैव संसदीय इतिहास भी याद रखेगा। अब 18वीं लोकसभा में भी ओम बिड़ला की अध्यक्षता के दौरान देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐतिहासिक कदमों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा की इस लोकसभा से देश के 140 करोड लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं बहुत हैं जिन्हें पूरा करने में ओम बिड़ला सक्षम होंगे ऐसा उनका अटल विश्वास है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में भी बिड़ला के अनुभव से सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलने के साथ संसदीय मर्यादाओं का एक नूतन अध्याय रचा जाएगा।

प्लास्टिक के चावलों की हो जांच , उठाई मांग

जयन्त प्रतिनिधि। लैंसडौन : सामाजिक संगठन जनसेवा मंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी सस्ता गल्लों से प्लास्टिक के चावल वितरित किये जा रहे है। संगठन ने उपजिलाधिकारी लैंसडौन को ज्ञापन सौंपकर चावलों की जांच कराने की मांग की है।

जनसेवा मंच के संयोजक मनोज दास ने उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कहा कि तहसील लैंसडौन के अन्तर्गत खाद्य आपूर्ति विभाग के सरकारी सस्ते गल्लों के द्वारा मिलावटी चावल उपभोक्ताओं को खिलाया जा रहा है। जनता को अंदेशा है कि ये प्लास्टिक के चावल हैं। मिलावट होने के कारण लोग इन चावलों को खाने से डर रहे हैं। इन चावलों की बनावट और प्रकृति सामान्य चावलों से अलग है। उन्होंने बताया कि मिलावट खोरों द्वारा गरीब जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन मिलावटी चावलों की जांच संबंधित सक्षम एजेंसी या विभाग से होना अनिवार्य है। यदि जांच में ये प्लास्टिक के चावल साबित हुए तो मिलावट खोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय। ज्ञापन देने वालों में सन्तूदास, संजय शाह, अशोक नेगी, राम सिंह, अनुराग ध्यानी, विनोद आदि शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने 170 अभ्यर्थियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

165 सहायक अभियंताओं और 05 कनिष्ठ सहायकों को दी गई नियुक्ति

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 170 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। जिसमें 165 सहायक अभियंताओं और 05 कनिष्ठ सहायक शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में सभी चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको अपने कार्यक्षेत्र में शत प्रतिशत योगदान देकर अपने माता-पिता और राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वे कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य है कि, सभी अभ्यर्थियों को चयन वर्ष का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 03 सालों में राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इन 03 वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14 हजार 800

नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं। इस कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई के प्राविधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय से ही युवा राजनीति में कार्य किया है, युवा वर्ग हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी सहायक अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी मन में यह भाव लेकर चलें कि कार्यक्षेत्र में हर समय नई चीजें, सीखने को मिलेगी, उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विनीत कुमार, कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

165 सहायक अभियंताओं और05 कनिष्ठ सहायकों को दी गई नियुक्ति

सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 24, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 44, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पद पर 20, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) के पद पर 41, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (आवास विभाग) के पद पर 14, सहायक अभियंता, यांत्रिक अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 10, सहायक अभियंता, कृषि अभियंत्रण (लघु सिंचाई विभाग) के पद पर 06, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (लघु सिंचाई विभाग) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, (ऊर्जा विभाग) के पद पर 02-02 एवं सहायक अभियंता, विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 01-01 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469 / 79
फोन / फैक्स 01382—222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com